

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

In this chapter we study the story of this relationship between the external and the internal politics by focussing on

- **the international context that shaped India's external relations;**
- **the operational principles that informed the country's foreign policy;**
- **the history of India's relations with China and Pakistan; and**
- **the evolution of India's nuclear policy.**

इस अध्याय में हम अंदरूनी और बाहरी राजनीति के इसी रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में चर्चा की जाएगी कि:

- भारत के विदेश संबंधों ने किन अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आकार ग्रहण किया;
- भारत की विदेश नीति किन सिद्धांतों से निर्देशित हुई;
- चीन और पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते कैसे रहे; और
- भारत की परमाणु नीति का उद्भव किन स्थितियों में हुआ?

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

International context

India was born in a very trying and challenging international context. The world had witnessed a devastating war and was grappling with issues of reconstruction; yet another attempt to establish an international body was underway; many new countries were emerging as a result of the collapse of colonialism; and most new nations were trying to come to terms with the twin challenges of welfare and democracy. Free India's foreign policy reflected all these concerns in the period immediately after Independence. Apart from these factors at the global level, India had its own share of concerns.

अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ

भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आजाद हुआ था। दुनिया महायुद्ध की तबाही से अभी बाहर निकली थी और उसके सामने पुनर्निर्माण का सवाल प्रमुख था। एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाने के प्रयास हो रहे थे और उपनिवेशवाद की समाप्ति के फलस्वरूप दुनिया के नक्शे पर नए देश नमूदार हो रहे थे। नए देशों के सामने लोकतंत्र कायम करने और अपनी जनता की भलाई करने की दोहरी चुनौती थी। स्वतंत्रता के तुरंत बाद भारत ने जो विदेश नीति अपनाई उनमें हम इन सारे सरोकारों की झलक पाते हैं। वैश्विक स्तर के इन सरोकारों के अलावा भारत की कुछ अपनी चिंताएँ भी थीं।

The British government left behind the legacy of many international disputes; Partition created its own pressures, and the task of poverty alleviation was already waiting for fulfilment. This was the overall context in which India started participating in the world affairs as an independent nation-state.

अंग्रेजी सरकार अपने पीछे अंतर्राष्ट्रीय विवादों की एक पूरी विरासत छोड़ गई थी; बँटवारे के कारण अलग से दवाब पैदा हुए थे और गरीबी मिटाने का काम सामने मुँह बाए खड़ा था। कुल जमा इन्हीं संदर्भों के बीच भारत ने एक स्वतंत्र राष्ट्र-राज्य के रूप में अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भागीदारी शुरू की।

As a nation born in the backdrop of the world war, India decided to conduct its foreign relations with an aim to respect the sovereignty of all other nations and to achieve security through the maintenance of peace. This aim finds an echo in the Directive Principles of State Policy.

एक राष्ट्र के रूप में भारत का जन्म विश्वयुद्ध की पृष्ठभूमि में हुआ था। ऐसे में भारत ने अपनी विदेश नीति में अन्य सभी देशों की संप्रभुता का सम्मान करने और शांति कायम करके अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य सामने रखा। इस लक्ष्य की प्रतिध्वनि संविधान के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में सुनाई देती है।

Just as both internal and external factors guide the behaviour of an individual or a family, both domestic and international environment influence the foreign policy of a nation. The developing countries lack the required resources to effectively advocate their concerns in the international system. So they pursue more modest goals than the advanced states. They focus more on peace and development in their own neighbourhood. Moreover, their economic and security dependence on the more powerful states occasionally influences their foreign policy

जिस तरह किसी व्यक्ति या परिवार के व्यवहारों को अंदरूनी और बाहरी कारक निर्देशित करते हैं उसी तरह एक देश की विदेश नीति पर भी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय वातावरण का असर पड़ता है। विकासशील देशों के पास अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के भीतर अपने सरोकारों को पूरा करने के लिए जरूरी संसाधनों का अभाव होता है। इसके चलते वे बड़े-चढ़े देशों की अपेक्षा बड़े सीधे-सादे लक्ष्यों को लेकर अपनी विदेश नीति तय करते हैं। ऐसे देशों का जोर इस बात पर होता है कि उनके पड़ोस में अमन-चैन कायम रहे और विकास होता रहे। इसके अतिरिक्त, विकासशील देश आर्थिक और सुरक्षा की दृष्टि से ज्यादा ताकतवर देशों पर निर्भर होते हैं। इस निर्भरता का भी उनकी विदेश नीति पर जब-तब असर पड़ता है।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

In the period immediately after the Second World War, many developing nations chose to support the foreign policy preferences of the powerful countries who were giving them aid or credits. This resulted in the division of countries of the world into two clear camps. One was under the influence of the United States and its western allies and the other was under the influence of the then Soviet Union.

दूसरे विश्वयुद्ध के तुरंत बाद के दौर में अनेक विकासशील देशों ने ताकतवर देशों की मर्जी को ध्यान में रखकर अपनी विदेश नीति अपनाई क्योंकि इन देशों से इन्हें अनुदान अथवा कर्ज मिल रहा था। इस वजह से दुनिया के विभिन्न देश दो खेमों में बँट गए। एक खेमा संयुक्त राज्य अमरीका और उसके समर्थक देशों के प्रभाव में रहा तो दूसरा खेमा सोवियत संघ के प्रभाव में।

The Policy of non-alignment

The Indian national movement was not an isolated process. It was a part of the worldwide struggle against colonialism and imperialism. It influenced the liberation movements of many Asian and African countries. Prior to India's Independence, there were contacts between the nationalist leaders of India and those of other colonies, united as they were in their common struggle against colonialism and imperialism. The creation of the Indian National Army (INA) by Netaji Subhash Chandra Bose during the Second World War was the clearest manifestation of the linkages established between India and overseas Indians during the freedom struggle.

गुटनिरपेक्षता की नीति

भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप में कोई स्वतंत्र घटना नहीं है। पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्ति आंदोलनों पर हुआ। आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य उपनिवेशों में मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के संपर्क में थे। ये सभी नेता आखिर उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध एक साज़ी लड़ाई लड़ रहे थे। नेताजी सुभाषचंद्र बोस ने दूसरे विश्वयुद्ध के दौरान 'इंडियन नेशनल आर्मी' (आई. एन.ए.) का गठन किया था। इससे साफ़ त-साफ़ त ज़ाहिर होता है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारत के संबंध विदेशों में रह रहे भारतीयों से बन चुके थे।

The foreign policy of a nation reflects the interplay of domestic and external factors. Therefore, the noble ideals that inspired India's struggle for freedom influenced the making of its foreign policy. But India's attainment of independence coincided with the beginning of the Cold War era. As you read in the first chapter of the book, Contemporary World Politics, this period was marked by the political, economic, and military confrontation at the global level between the two blocs led by the superpowers, the US and the USSR. The same period also witnessed developments like the establishment of the UN, the creation of nuclear weapons, the emergence of Communist China, and the beginning of decolonisation. So India's leadership had to pursue its national interests within the prevailing international context.

किसी राष्ट्र की विदेश नीति से उसके अंदरूनी और बाहरी सरोकारों की झलक मिलती है। भारत का स्वतंत्रता आंदोलन जिन उदात्त विचारों से प्रेरित था उनका असर भारत की विदेश नीति पर भी पड़ा। बहरहाल, भारत को जिस वक्त आज़ादी हासिल हुई उस समय शीतयुद्ध का दौर भी शुरू हो चुका था। आप 'समकालीन विश्व राजनीति' की किताब के पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं कि शीतयुद्ध के दौर में दुनिया के देश दो खेमों में बँट रहे थे। एक खेमे का अगुआ संयुक्त राज्य अमरीका था और दूसरे का सोवियत संघ। दोनों खेमों के बीच विश्वस्तर पर आर्थिक, राजनीतिक और सैन्य टकराव जारी था। इसी दौर में संयुक्त राष्ट्र संघ भी अस्तित्व में आया; परमाणु हथियारों का निर्माण शुरू हुआ; चीन में कम्युनिस्ट शासन की स्थापना हुई। अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया भी इसी दौर में आरंभ हुई थी। भारत के नेताओं को अपने राष्ट्रीय हित इसी संदर्भ के दायरे में साधने थे।

Nehru's role

The first Prime Minister, Jawaharlal Nehru played a crucial role in setting the national agenda. He was his own foreign minister. Thus both as the Prime Minister and the Foreign Minister, he exercised profound influence in the formulation and implementation of India's foreign policy from 1946 to 1964. The three major objectives of Nehru's foreign policy were to preserve the hard-earned sovereignty, protect territorial integrity, and promote rapid economic development. Nehru wished to achieve these objectives through the strategy of nonalignment.

नेहरू की भूमिका भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्रीय एजेंडा तय करने में निर्णायक भूमिका निभाई। वे प्रधानमंत्री के साथ-साथ विदेश मंत्री भी थे। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री के रूप में 1946 से 1964 तक उन्होंने भारत की विदेश नीति की रचना और क्रियान्वयन पर गहरा प्रभाव डाला। नेहरू की विदेश नीति के तीन बड़े उद्देश्य थे— कठिन संघर्ष से प्राप्त संप्रभुता को बचाए रखना, क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखना और तेज़ रफ्तार से आर्थिक विकास करना। नेहरू इन उद्देश्यों को गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाकर हासिल करना चाहते थे।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

There were, of course, parties and groups in the country that believed that India should be more friendly with the bloc led by the US because that bloc claimed to be pro-democracy. Among those who thought on these lines were leaders like Dr Ambedkar. Some political parties, which were opposed to communism, also wanted India to follow a pro-US foreign policy. These included the Bharatiya Jan Sangh and later the Swatantra Party. But Nehru possessed considerable leeway in formulating foreign policy.

उन दिनों देश में कुछ पार्टियां और समूह ऐसे भी थे जिनका मानना था कि भारत को अमरीकी खेमे के साथ ज्यादा नज़दीकी बढ़ानी चाहिए क्योंकि इस खेमे की प्रतिष्ठा लोकतंत्र के हिमायती के रूप में थी। इस धारा पर सोचने वालों में डा. भीमराव अंबेडकर भी शामिल थे। साम्यवाद की विरोधी कुछ राजनीतिक पार्टियां भी चाहती थीं कि भारत अपनी विदेश नीति अमरीका के पक्ष में बनाए। ऐसे दलों में भारतीय जनसंघ और स्वतंत्र पार्टी प्रमुख थे। लेकिन, विदेश नीति को तैयार करने के मामले में नेहरू को खासी बढ़त हासिल थी।

Distance from two camps

The foreign policy of independent India vigorously pursued the dream of a peaceful world by advocating the policy of non-alignment, by reducing Cold War tensions and by contributing human resources to the UN peacekeeping operations. You might ask why India did not join either of the two camps during the Cold War era. India wanted to keep away from the military alliances led by US and Soviet Union against each other. As you read in the book, Contemporary World Politics, during the Cold War, the US-led North Atlantic Treaty Organisation (NATO) and the Soviet-led Warsaw Pact came into existence. India advocated non-alignment as the ideal foreign policy approach.

दो खेमों से दूरी

आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था और इसके लिए भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति का पालन किया। भारत ने इसके लिए शीतयुद्ध से उपजे तनाव को कम करने की कोशिश की और संयुक्त राष्ट्र संघ के शांति-अभियानों में अपनी सेना भेजी। आप पूछ सकते हैं कि शीतयुद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में क्यों शामिल नहीं हुआ? भारत, अमरीका और सोवियत संघ की अगुवाई वाले सैन्य गठबंधनों से अपने को दूर रखना चाहता था। 'समकालीन विश्व राजनीति' की किताब में आप पढ़ चुके हैं कि शीतयुद्ध के समय अमरीका ने उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (NATO) और सोवियत संघ ने इसके जवाब में 'वारसा पक्ट' नामक संधि संगठन बनाया था। भारत ने गुटनिरपेक्षता की नीति को आदर्श माना।

This was a difficult balancing act and sometimes the balance did not appear perfect. In 1956 when Britain attacked Egypt over the Suez Canal issue, India led the world protest against this neo-colonial invasion. But in the same year when the USSR invaded Hungary, India did not join its public condemnation. Despite such a situation, by and large India did take an independent stand on various international issues and could get aid and assistance from members of both the blocs.

संतुलन साधने की यह कठिन कोशिश थी और कभी-कभी संतुलन बहुत कुछ नहीं भी सध पाता था। 1956 में जब ब्रिटेन ने स्वेज नहर के मामले को लेकर मिस्र पर आक्रमण किया तो भारत ने इस नव-औपनिवेशिक हमले के विरुद्ध विश्वव्यापी विरोध की अगुवाई की। इसी साल सोवियत संघ ने हंगरी पर आक्रमण किया था लेकिन भारत ने सोवियत संघ के इस कदम की सार्वजनिक निंदा नहीं की। ऐसी स्थिति के बावजूद, कमोबेश भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर स्वतंत्र रवैया अपनाया। उसे दोनों खेमों के देशों ने सहायता और अनुदान दिए।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

While India was trying to convince the other developing countries about the policy of non-alignment, Pakistan joined the US-led military alliances. The US was not happy about India's independent initiatives and the policy of non-alignment. Therefore, there was a considerable unease in Indo-US relations during the 1950s. The US also resented India's growing partnership with the Soviet Union.

भारत अभी बाकी विकासशील देशों को गुटनिरपेक्षता की नीति के बारे में आश्वस्त करने में लगा था कि पाकिस्तान अमरीकी नेतृत्व वाले सैन्य-गठबंधन में शामिल हो गया। इस वजह से 1950 के दशक में भारत-अमरीकी संबंधों में खटास पैदा हो गई। अमरीका, सोवियत संघ से भारत की बढ़ती हुई दोस्ती को लेकर भी नाराज था।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

You have studied in the last chapter, the strategy of planned economic development adopted by India. This policy emphasised import-substitution. The emphasis on developing a resource base also meant that export oriented growth was limited. This development strategy limited India's economic interaction with the outside world.

आपने पिछले अध्याय में पढ़ा । कि भारत ने नियोजित विकास की रणनीति अपनाई थी। इस नीति में ज़ोर आयात को कम करने पर था। इसमें संसाधन-आधार तैयार करने पर ज़ोर दिया गया। इसके परिणामस्वरूप निर्यात के मामले में भी प्रगति बड़ी सीमित थी। विकास की इस रणनीति के कारण बाहरी दुनिया से भारत का आर्थिक लेन-देन बड़ा सीमित था।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

Afro-Asian unity

Yet, given its size, location and power potential, Nehru envisaged a major role for India in world affairs and especially in Asian affairs. His era was marked by the establishment of contacts between India and other newly independent states in Asia and Africa. Throughout the 1940s and 1950s, Nehru had been an ardent advocate of Asian unity. Under his leadership, India convened the Asian Relations Conference in March 1947, five months ahead of attaining its independence. India made earnest efforts for the early realisation of freedom of Indonesia from the Dutch colonial regime by convening an international conference in 1949 to support its freedom struggle.

एफ्रो-एशियाई एकता

भारत के आकार, अवस्थिति और शक्ति-संभावना को भाँपकर नेहरू ने विश्व के मामलों, खासकर एशियाई मामलों में भारत के लिए बड़ी भूमिका निभाने का स्वप्न देखा था। नेहरू के दौर में भारत ने एशिया और अफ्रीका के नव-स्वतंत्र देशों के साथ संपर्क बनाए। 1940 और 1950 के दशकों में नेहरू बड़े मुखर स्वर में एशियाई एकता की पैरोकारी करते रह। नेहरू की अगुवाई में भारत ने 1947 के मार्च में ही एशियाई संबंध सम्मेलन (एशियन रिलेशंस कांफ्रेंस) का आयोजन कर डाला था जबकि अभी भारत को आज़ादी मिलने में पाँच महीने शेष थे। भारत ने इंडोनेशिया की आज़ादी के लिए भरपूर प्रयास किए। भारत चाहता था कि इंडोनेशिया डच औपनिवेशिक शासन से यथासंभव शीघ्र मुक्त हो जाए। इसके लिए भारत ने 1949 में इंडोनेशिया के स्वतंत्रता-संग्राम के समर्थन में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया।

firmly opposed racism, especially apartheid in South Africa. The AfroAsian conference held in the Indonesian city of Bandung in 1955, commonly known as the Bandung Conference, marked the zenith of India's engagement with the newly independent Asian and African nations. The Bandung Conference later led to the establishment of the NAM. The First Summit of the NAM was held in Belgrade in September 1961. Nehru was a co-founder of the NAM (See Chapter 1 of Contemporary World Politics).

भारत अनौपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का प्रबल समर्थक था और उसने पूरी दृढ़ता से नस्लवाद का, खासकर दक्षिण अफ्रीका में जारी रंगभेद का विरोध किया। इंडोनेशिया के एक शहर बांडुंग में एफ्रो-एशियाई सम्मेलन 1955 में हुआ। आमतौर पर हम इसे बांडुंग-सम्मेलन के नाम से जानते हैं। अफ्रीका और एशिया के नव-स्वतंत्र देशों के साथ भारत के बढ़ते संपर्क का यह चरम बिंदु था। बांडुंग-सम्मेलन में ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव पड़ी। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 के सितंबर में बेलग्रेड में हुआ। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना में नेहरू की महती भूमिका रही थी। (देखें, 'समकालीन विश्व राजनीति' अध्याय-1)

TIBET

The plateau of the central Asian region called Tibet is one of the major issues that historically caused tension between India and China. From time to time in history, China had claimed administrative control over Tibet. And from time to time, Tibet was independent too. In 1950, China took over control of Tibet. Large sections of the Tibetan population opposed this takeover. India tried to persuade China to recognise Tibet's claims for independence. When the Panchsheel agreement was signed between India and China in 1954, through one of its clauses about respecting each other's territorial integrity and sovereignty, India conceded China's claim over Tibet.

तिब्बत

यह मध्य एशिया का मशहूर पठार है। ऐतिहासिक रूप से तिब्बत भारत और चीन के बीच विवाद का एक बड़ा मसला रहा है। अतीत में समय समय पर चीन ने तिब्बत पर अपना प्रशासनिक नियंत्रण जताया और कई दफा तिब्बत आज़ाद भी हुआ। 1950 में चीन ने तिब्बत पर नियंत्रण कर लिया। तिब्बत के ज़्यादातर लोगों ने चीनी कब्ज़े का विरोध किया। 1954 में जब भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर हुए तो इसके प्रावधानों में एक बात यह भी शामिल थी कि दोनों देश एक-दूसरे की क्षेत्रीय संप्रभुता का सम्मान करेंगे। चीन ने इस प्रावधान का अर्थ लगाया कि भारत तिब्बत पर चीनी दावेदारी की बात को स्वीकार कर रहा है।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

The Tibetan spiritual leader Dalai Lama accompanied the Chinese Premier Zhou Enlai during the official Chinese visit to India in 1956. He informed Nehru about the worsening situation in Tibet. But China had already assured India that Tibet will be given greater autonomy than enjoyed by any other region of China. In 1958, there was armed uprising in Tibet against China's occupation. This was suppressed by the Chinese forces.

1956 में चीनी शासनाध्यक्ष चाऊ एन लाई भारत के आधिकारिक दौरे पर आए तो साथ ही साथ तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा भी भारत पहुँचे। उन्होंने तिब्बत की बिगड़ती स्थिति की जानकारी नेहरू को दी। चीन आश्वासन दे चुका था कि तिब्बत को चीन के अन्य इलाकों से कहीं ज़्यादा स्वायत्तता दी जाएगी। 1958 में चीनी आधिपत्य के विरुद्ध तिब्बत में सशस्त्र विद्रोह हुआ। इस विद्रोह को चीन की सेनाओं ने दबा दिया।

Sensing that the situation had become worse, in 1959, the Dalai Lama crossed over into the Indian border and sought asylum which was granted. The Chinese government strongly protested against this. Over the last half century, a large number of Tibetans have also sought refuge in India and many other countries of the world. In India, particularly in Delhi, there are large settlements of Tibetan refugees. Dharmashala in Himachal Pradesh is perhaps the largest refuge settlement of Tibetans in India.

स्थिति बिगड़ती देखकर तिब्बत के पारंपरिक नेता दलाई लामा ने सीमा पारकर भारत में प्रवेश किया और 1959 में भारत से शरण माँगी। भारत ने दलाई लामा को शरण दे दी। चीन ने भारत के इस कदम का कड़ा विरोध किया। पिछले 50 सालों में बड़ी संख्या में तिब्बती जनता ने भारत और दुनिया के अन्य देशों में शरण ली है। भारत में (खासकर दिल्ली में) तिब्बती शरणार्थियों की बड़ी-बड़ी बस्तियाँ हैं। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में संभवतया तिब्बती शरणार्थियों की सबसे बड़ी बस्ती है। दलाई लामा ने भी भारत में धर्मशाला को ही अपना निवास-स्थान बनाया है।

In the 1950s and 1960s many political leaders and parties in India including the Socialist Party and the Jan Sangh supported the cause of Tibet's independence.

1950 और 1960 के दशक में भारत के अनेक राजनीतिक दल और राजनेताओं ने तिब्बत की आज़ादी के प्रति अपना समर्थन जताया। इन दलों में सोशलिस्ट पार्टी और जनसंघ शामिल हैं।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

China has created the Tibet autonomous region, which is an integral part of China. Tibetans oppose the Chinese claim that Tibet is part of Chinese territory. They also oppose the policy of bringing into Tibet more and more Chinese settlers. Tibetans dispute China's claim that autonomy is granted to the region. They think that China wants to undermine the traditional religion and culture of Tibet.

चीन ने 'स्वायत्त तिब्बत क्षेत्र' बनाया है और इस इलाके को वह चीन का अभिन्न अंग मानता है। तिब्बती जनता चीन के इस दावे को नहीं मानती कि तिब्बत चीन का अभिन्न अंग है। ज्यादा से ज्यादा संख्या में चीनी बाशिंदों को तिब्बत लाकर वहां बसाने की चीन की नीति का तिब्बती जनता ने विरोध किया। तिब्बती चीन के इस दावे को भी नकारते हैं कि तिब्बत को स्वायत्तता दी गई है। वे मानते हैं कि तिब्बत की पारंपरिक संस्कृति और धर्म को नष्ट करके चीन वहां साम्यवाद फैलाना चाहता है।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

Peace and conflict with China

Unlike its relationship with Pakistan, free India began its relationship with China on a very friendly note. After the Chinese revolution in 1949, India was one of the first countries to recognise the communist government. Nehru felt strongly for this neighbour that was coming out of the shadow of western domination and helped the new government in international fora. Some of his colleagues, like Vallabhbhai Patel, were worried about a possible Chinese aggression in future. But Nehru thought it was 'exceedingly unlikely' that India will face an attack from China. For a very long time, the Chinese border was guarded by para-military forces, not the army.

चीन के साथ शांति और संघर्ष

पाकिस्तान के साथ अपने संबंधों के विपरीत आज़ाद भारत ने चीन के साथ अपने रिश्तों की शुरुआत बड़े दोस्ताना ढंग से की। चीनी क्रांति 1949 में हुई थी। इस क्रांति के बाद भारत, चीन की कम्युनिस्ट सरकार को मान्यता देने वाले पहले देशों में एक था। पश्चिमी प्रभुत्व के चंगुल से निकलने वाले इस देश को लेकर नेहरू के हृदय में गहरे भाव थे और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फ़लक पर इस सरकार की मदद की। नेहरू के कुछ सहयोगियों-मसलन सरदार बल्लभ भाई पटेल को आशंका थी कि आगामी दिनों में चीन भारत पर चढ़ाई कर सकता है। लेकिन नेहरू सोच रहे थे कि भारत पर चीन के आक्रमण की संभावना दूर-दूर तक नहीं है। बहुत दिनों से भारत की चीन से लगती सीमा पर सेना के बजाय अर्द्ध-सैनिक बल रखवाली कर रहे थे।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

The joint enunciation of Panchsheel, the Five Principles of Peaceful Coexistence, by the Indian Prime Minister Nehru and the Chinese Premier Zhou Enlai on 29 April 1954 was a step in the direction of stronger relationship between the two countries. Indian and Chinese leaders visited each other's country and were greeted by large and friendly crowds.

शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के पाँच सिद्धांतों यानी पंचशील की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नेहरू और चीन के प्रमुख चारु एन लाई ने संयुक्त रूप से 29 अप्रैल 1954 में की। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध की दिशा में यह एक अगला कदम था। भारत और चीन के नेता एक-दूसरे के देश का दौरा करते थे और उनके स्वागत में बड़ी भीड़ जुटती थी।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

The Chinese invasion, 1962

Two developments strained this relationship. China annexed Tibet in 1950 and thus removed a historical buffer between the two countries. Initially, the government of India did not oppose this openly. But as more information came in about the suppression of Tibetan culture, the Indian government grew uneasy. The Tibetan spiritual leader, the Dalai Lama, sought and obtained political asylum in India in 1959. China alleged that the government of India was allowing anti-China activities to take place from within India.

चीन का आक्रमण, 1962

चीन के साथ भारत के इस दोस्ताना रिश्ते में दो कारणों से खटास आई। चीन ने 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया। इससे भारत और चीन के बीच ऐतिहासिक रूप से जो एक मध्यवर्ती राज्य बना चला आ रहा था, वह खत्म हो गया। शुरू-शुरू में भारत सरकार ने चीन के इस कदम का खुले तौर पर विरोध नहीं किया। बहरहाल, तिब्बत की संस्कृति को कुचलने की खबरें जैसे-जैसे सामने आने लगी, वैसे-वैसे भारत की बेचैनी भी बढ़ी। तिब्बत के धार्मिक नेता दलाई लामा ने भारत से राजनीतिक शरण माँगी और 1959 में भारत ने उन्हें शरण दे दी। चीन ने आरोप लगाया कि भारत सरकार अंदरूनी तौर पर चीन विरोधी गतिविधियों को हवा दे रही है।

A little earlier, a boundary dispute had surfaced between India and China. India claimed that the boundary was a matter settled in colonial time, but China said that any colonial decision did not apply. The main dispute was about the western and the eastern end of the long border. China claimed two areas within the Indian territory: Aksai-chin area in the Ladakh region of Jammu and Kashmir and much of the state of Arunachal Pradesh in what was then called NEFA (North Eastern Frontier Agency).

इससे कुछ दिनों पहले भारत और चीन के बीच एक सीमा-विवाद भी उठ खड़ा हुआ था। भारत का दावा था कि चीन के साथ सीमा-रेखा का मामला अंग्रेजी-शासन के समय ही सुलझाया जा चुका है। लेकिन चीन की सरकार का कहना था कि अंग्रेजी शासन के समय का फैसला नहीं माना जा सकता। मुख्य विवाद चीन से लगी लंबी सीमा-रेखा के पश्चिमी और पूर्वी छोर के बारे में था। चीन ने भारतीय भू-क्षेत्र में पड़ने वाले दो इलाकों—जम्मू-कश्मीर के लद्दाख वाले हिस्से के अक्साई-चीन और अरुणाचल प्रदेश—के अधिकांश हिस्सों पर अपना अधिकार जताया। अरुणाचल प्रदेश को उस समय नेफा या उत्तर-पूर्वी सीमांत कहा जाता था।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

Between 1957 and 1959, the Chinese occupied the Aksai-chin area and built a strategic road there. Despite a very long correspondence and discussion among top leaders, these differences could not be resolved. Several small border skirmishes between the armies of the two countries took place.

1957 से 1959 के बीच चीन ने अक्साई-चीन इलाके पर कब्ज़ा कर लिया और इस इलाके में उसने रणनीतिक बढ़त हासिल करने के लिए एक सड़क बनाई। दोनों देशों के शीर्ष नेताओं के बीच लंबी-लंबी चर्चाएँ और बातचीत चली लेकिन इसके बावजूद मतभेद को सुलझाया नहीं जा सका। दोनों देशों की सेनाओं के बीच सीमा पर कई बार झड़प हुई।

Do you remember the Cuban Missile Crisis in Chapter One of the Contemporary World Politics? While the entire world's attention was on this crisis involving the two superpowers, China launched a swift and massive invasion in October 1962 on both the disputed regions. The first attack lasted one week and Chinese forces captured some key areas in Arunachal Pradesh. The second wave of attack came next month. While the Indian forces could block the Chinese advances on the western front in Ladakh, in the east the Chinese managed to advance nearly to the entry point of Assam plains. Finally, China declared a unilateral ceasefire and its troops withdrew to where they were before the invasion began.

‘समकालीन विश्व राजनीति’ के पहले अध्याय में क्यूबा के मिसाइल-संकट की चर्चा की गई थी। क्या आपको इस घटना की याद है? जिस समय पूरे विश्व का ध्यान दो महाशक्तियों की तनातनी से पैदा इस संकट की तरफ लगा हुआ था, ठीक उसी समय चीन ने 1962 के अक्टूबर में दोनों विवादित क्षेत्रों पर बड़ी तेज़ी तथा व्यापक स्तर पर हमला किया। पहला हमला एक हफ्ते तक चला और इस दौरान चीनी सेना ने अरुणाचल प्रदेश के कुछ महत्वपूर्ण इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। हमले का अगला दौर नवंबर महीने में शुरू हुआ। लद्दाख से लगे पश्चिमी मोर्चे पर भारतीय सेना ने चीन की बढ़त रोक दी लेकिन पूर्व में चीनी सेना आगे बढ़ते हुए असम के मैदानी हिस्से के प्रवेशद्वार तक पहुँच गई। आखिरकार, चीन ने एकतरफा युद्धविराम घोषित किया और चीन की सेनाएँ उस मुकाम पर लौट गईं जहाँ वे हमले से पहले के वक्त में तैनात थीं।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

The China war dented India's image at home and abroad. India had to approach the Americans and the British for military assistance to tide over the crisis. The Soviet Union remained neutral during the conflict. It induced a sense of national humiliation and at the same time strengthened a spirit of nationalism. Some of the top army commanders either resigned or were retired. Nehru's close associate and the then Defence Minister, V. Krishna Menon, had to leave the cabinet.

चीन-युद्ध से भारत की छवि को देश और विदेश दोनों ही जगह धक्का लगा। इस संकट से उबरने के लिए भारत को अमरीका और ब्रिटेन दोनों से सैन्य मदद की गुहार लगानी पड़ी। सोवियत संघ इस संकट की घड़ी में तटस्थ बना रहा। चीन-युद्ध से भारतीय राष्ट्रीय स्वाभिमान को चोट पहुँची लेकिन इसके साथ-साथ राष्ट्र-भावना भी बलवती हुई। कुछ प्रमुख सैन्य-कमांडरों ने या तो इस्तीफा दे दिया या अवकाश ग्रहण कर लिया। नेहरू के नजदीकी सहयोगी और तत्कालीन रक्षामंत्री वी.के. कृष्णामेनन को भी मंत्रिमंडल छोड़ना पड़ा।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

Nehru's own stature suffered as he was severely criticised for his naïve assessment of the Chinese intentions and the lack of military preparedness. For the first time, a no-confidence motion against his government was moved and debated in the Lok Sabha. Soon thereafter, the Congress lost some key by-elections to Lok Sabha. The political mood of the country had begun to change.

नेहरू की छवि भी थोड़ी धूमिल हुई। चीन के इरादों को समय रहते न भाँप सकने और सैन्य तैयारी न कर पाने को लेकर नेहरू की बड़ी आलोचना हुई। पहली बार, उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया और लोकसभा में इस पर बहस हुई। इसके तुरंत बाद, कांग्रेस ने कुछ महत्वपूर्ण उप-चुनावों में पटखनी खाई। देश का राजनीतिक मानस बदलने लगा था।

The Sino-Indian conflict affected the opposition as well. This and the growing rift between China and the Soviet Union created irreconcilable differences within the Communist Party of India (CPI). The pro-USSR faction remained within the CPI and moved towards closer ties with the Congress. The other faction was for sometime closer to China and was against any ties with the Congress. The party split in 1964 and the leaders of the latter faction formed the Communist Party of India (Marxist) (CPI-M). In the wake of the China war, many leaders of what became CPI (M) were arrested for being pro-China.

भारत चीन संघर्ष का असर विपक्षी दलों पर भी हुआ। इस युद्ध और चीन-सोवियत संघ के बीच बढ़ते मतभेद से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा) के अंदर बड़ी उठा-पटक मची। सोवियत संघ का पक्षधर खेमा भाकपा में ही रहा और उसने कांग्रेस के साथ नजदीकी बढ़ायी। दूसरा खेमा कुछ समय के लिए चीन का पक्षधर रहा और यह खेमा कांग्रेस के साथ किसी भी तरह की नजदीकी के खिलाफ़ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1964 में टूट गई। इस पार्टी के भीतर जो खेमा चीन का पक्षधर था उसने मार्क्सवादी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (सी. पी. आई. एम.-माकपा) बनाई। चीन-युद्ध के क्रम में माकपा के कई नेताओं को चीन का पक्ष लेने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

The war with China alerted the Indian leadership to the volatile situation in the Northeast region. Apart from being isolated and extremely underdeveloped, this region also presented India with the challenge of national integration and political unity. The process of its reorganisation began soon after the China war. Nagaland was granted statehood; Manipur and Tripura, though Union Territories, were given the right to elect their own legislative assemblies.

चीन के साथ हुए युद्ध ने भारत के नेताओं को पूर्वोत्तर की डावाँडोल स्थिति के प्रति सचेत किया। यह इलाका अत्यंत पिछड़ी दशा में था और अलग-थलग पड़ गया था। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिहाज से भी यह इलाका चुनौतीपूर्ण था। चीन-युद्ध के तुरंत बाद इस इलाके को नयी तरतीब में ढालने की कोशिशें शुरू की गईं। नगालैंड को प्रांत का दर्जा दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा हालाँकि केंद्र-शासित प्रदेश थे लेकिन उन्हें अपनी विधानसभा के निर्वाचन का अधिकार मिला।

Wars and Peace with Pakistan

In the case of Pakistan, the conflict started just after Partition over the dispute on Kashmir. You will read more about the dispute in Chapter 8. A proxy war broke out between the Indian and Pakistani armies in Kashmir during 1947 itself. But this did not turn into a full war. The issue was then referred to the UN. Pakistan soon emerged as a critical factor in India's relations with the US and subsequently with China.

पाकिस्तान के साथ युद्ध और शांति
कश्मीर मसले को लेकर पाकिस्तान के साथ बँटवारे के तुरंत बाद ही संघर्ष छिड़ गया था। आप इस विवाद के बारे में आठवें अध्याय में विस्तार से पढ़ सकते हैं। 1947 में ही कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सेनाओं के बीच एक छाया-युद्ध छिड़ गया था। बहरहाल, यह संघर्ष पूर्णव्यापी युद्ध का रूप न ले सका। यह मसला फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया गया। संयुक्त राज्य अमरीका और चीन के साथ भारत के संबंधों के लिहाज़ से पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण घटक रहा।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

The Kashmir conflict did not prevent cooperation between the governments of India and Pakistan. Both the governments worked together to restore the women abducted during Partition to their original families. A long-term dispute about the sharing of river waters was resolved through mediation by the World Bank. The India-Pakistan Indus Waters Treaty was signed by Nehru and General Ayub Khan in 1960. Despite all ups and downs in the Indo-Pak relations, this treaty has worked well.

कश्मीर के सवाल पर हुए संघर्ष के बावजूद भारत और पाकिस्तान की सरकारों के बीच सहयोग-संबंध कायम हुए। दोनों सरकारों ने मिल-जुल कर प्रयास किया कि बँटवारे के समय जो महिलाएँ अपहृत हुई थीं उन्हें अपने परिवार के पास वापस लौटाया जा सके। विश्व बैंक की मध्यस्थता से नदी जल में हिस्सेदारी को लेकर चला आ रहा एक लंबा विवाद सुलझा लिया गया। नेहरू और जनरल अयूब खान ने सिंधु नदी जल संधि पर 1960 में हस्ताक्षर किए। भारत-पाक संबंधों में नरमी-गरमी के बावजूद इस संधि पर ठीक-ठाक अमल होता रहा।

A more serious armed conflict between the two countries began in 1965. As you would read in the next chapter, by then Lal Bahadur Shastri had taken over as the Prime Minister. In April 1965 Pakistan launched armed attacks in the Rann of Kutch area of Gujarat. This was followed by a bigger offensive in Jammu and Kashmir in August/September. Pakistani rulers were hoping to get support from the local population there, but it did not happen. In order to ease the pressure on the Kashmir front, Shastri ordered Indian troops to launch a counter-offensive on the Punjab border. In a fierce battle, the Indian army reached close to Lahore.

दोनों देशों के बीच 1965 में कहीं ज्यादा गंभीर किस्म के सैन्य-संघर्ष की शुरुआत हुई। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इस वक्त लालबहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। 1965 के अप्रैल में पाकिस्तान ने गुजरात के कच्छ इलाके के रन में सैनिक हमला बोला। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में उसने अगस्त-सितंबर के महीने में बड़े पैमाने पर हमला किया। पाकिस्तान के नेताओं को उम्मीद थी कि जम्मू-कश्मीर की जनता उनका समर्थन करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कश्मीर के मोर्चे पर पाकिस्तानी सेना की बढ़त को रोकने के लिए प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने पंजाब की सीमा की तरफ से जवाबी हमला करने के आदेश दिए। दोनों देशों की सेनाओं के बीच घनघोर लड़ाई हुई और भारत की सेना आगे बढ़ते हुए लाहौर के नजदीक तक पहुँच गई।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

The hostilities came to an end with the UN intervention. Later, Indian Prime Minister Lal Bahadur Shastri and Pakistan's General Ayub Khan signed the Tashkent Agreement, brokered by the Soviet Union, in January 1966. Though India could inflict considerable military loss on Pakistan, the 1965 war added to India's already difficult economic situation.

संयुक्त राष्ट्र संघ के हस्तक्षेप से इस लड़ाई का अंत हुआ। बाद में, भारतीय प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में ताशकंद-समझौता हुआ। सोवियत संघ ने इसमें मध्यस्थ की भूमिका निभाई। हालाँकि 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान को बहुत ज्यादा सैन्य क्षति पहुँचाई लेकिन इस युद्ध से भारत की कठिन आर्थिक स्थिति पर और ज़्यादा बोझ पड़ा।

Bangladesh war, 1971

Beginning in 1970, Pakistan faced its biggest internal crisis. The country's first general election produced a split verdict – Zulfikar Ali Bhutto's party emerged a winner in West Pakistan, while the Awami League led by Sheikh Mujib-ur Rahman swept through East Pakistan. The Bengali population of East Pakistan had voted to protest against years of being treated as second class citizens by the rulers based in West Pakistan. The Pakistani rulers were not willing to accept the democratic verdict. Nor were they ready to accept the Awami League's demand for a federation.

बांग्लादेश युद्ध, 1971

1970 में पाकिस्तान के सामने एक गहरा अंदरूनी संकट आ खड़ा हुआ। पाकिस्तान के पहले आम चुनाव में खंडित जनादेश आया। जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी पश्चिमी पाकिस्तान में विजयी रही जबकि मुजीबुर्रहमान की पार्टी अवामी लीग ने पूर्वी पाकिस्तान में ज़ोरदार कामयाबी हासिल की। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के हाथों अपने साथ हुए दोयम दर्जे के नागरिक के बरताव के विरोध में पूर्वी पाकिस्तान की बंगाली जनता ने इस पार्टी को वोट दिया था। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। अवामी लीग एक परिसंघ बनाने की माँग कर रही थी लेकिन वे इस माँग को भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

Instead, in early 1971, the Pakistani army arrested Sheikh Mujib and unleashed a reign of terror on the people of East Pakistan. In response to this, the people started a struggle to liberate 'Bangladesh' from Pakistan. Throughout 1971, India had to bear the burden of about 80 lakh refugees who fled East Pakistan and took shelter in the neighbouring areas in India. India extended moral and material support to the freedom struggle in Bangladesh. Pakistan accused India of a conspiracy to break it up.

इसकी जगह पाकिस्तानी सेना ने 1971 में शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया और पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म ढाने शुरू किए। जवाब में पूर्वी पाकिस्तान की जनता ने अपने इलाके यानी मौजूदा बांग्लादेश को पाकिस्तान से मुक्त कराने के लिए संघर्ष छेड़ दिया। 1971 में पूरे साल भारत को 80 लाख शरणार्थियों का बोझ वहन करना पड़ा। ये शरणार्थी पूर्वी पाकिस्तान से भागकर भारत के नजदीकी इलाकों में शरण लिए हुए थे। भारत ने बांग्लादेश के 'मुक्ति संग्राम' को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता दी। पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि भारत उसे तोड़ने की साजिश कर रहा है।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

Support for Pakistan came from the US and China. The US-China rapprochement that began in the late 1960s resulted in a realignment of forces in Asia. Henry Kissinger, the adviser to the US President Richard Nixon, made a secret visit to China via Pakistan in July 1971. In order to counter the US-Pakistan-China axis, India signed a 20-year Treaty of Peace and Friendship with the Soviet Union in August 1971. This treaty assured India of Soviet support if the country faced any attack.

पाकिस्तान को अमरीका और चीन ने मदद की । 1960 के दशक में अमरीका और चीन के बीच संबंधों को सामान्य करने की कोशिश चल रही थी और इससे एशिया में सत्ता-समीकरण नया रूप ले रहा था। अमरीकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के सलाहकार हेनरी किसिंजर ने 1971 के जुलाई में पाकिस्तान होते हुए गुपचुप चीन का दौरा किया। अमरीका-पाकिस्तान-चीन की धुरी बनती देख भारत ने इसके जवाब में सोवियत संघ के साथ 1971 में शांति और मित्रता की एक 20-वर्षीय संधि पर दस्तखत किए। संधि से भारत को इस बात का आश्वासन मिला कि हमला होने की सूरत में सोवियत संघ भारत की मदद करेगा।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

After months of diplomatic tension and military build-up, a full-scale war between India and Pakistan broke out in December 1971. Pakistani aircrafts attacked Punjab and Rajasthan, while the army moved on the Jammu and Kashmir front. India retaliated with an attack involving the air force, navy and the army on both the Western and the Eastern front. Welcomed and supported by the local population, the Indian army made rapid progress in East Pakistan.

महीनों राजनयिक तनाव और सैन्य तैनाती के बाद 1971 के दिसंबर में भारत और पाकिस्तान के बीच एक पूर्णव्यापी युद्ध छिड़ गया। पाकिस्तान के लड़ाकू विमानों ने पंजाब और राजस्थान पर हमले किए जबकि उसकी सेना ने जम्मू-कश्मीर में अपना मोर्चा खोला। जवाब में भारत ने अपनी वायुसेना, नौसेना और थलसेना के बूते पश्चिमी और पूर्वी मोर्चों से कार्रवाई की। स्थानीय लोगों के समर्थन और स्वागत के बीच भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में तेज़ी से आगे बढ़ी।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

Within ten days the Indian army had surrounded Dhaka from three sides and the Pakistani army of about 90,000 had to surrender. With Bangladesh as a free country, India declared a unilateral ceasefire. Later, the signing of the Shimla Agreement between Indira Gandhi and Zulfikar Ali Bhutto on 3 July 1972 formalised the return of peace.

दस दिनों के अंदर भारतीय सेना ने ढाका को तीन तरफ से घेर लिया और अपने 90,000 सैनिकों के साथ पाकिस्तानी सेना को आत्म-समर्पण करना पड़ा। बांग्लादेश के रूप में एक स्वतंत्र राष्ट्र के उदय के साथ भारतीय सेना ने अपनी तरफ से एकतरफा युद्ध-विराम घोषित कर दिया। बाद में, 3 जुलाई 1972 को इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच शिमला-समझौते पर दस्तखत हुए और इससे अमन की बहाली हुई।

A decisive victory in the war led to national jubilation. Most people in India saw this as a moment of glory and a clear sign of India's growing military prowess. As you would read in the next chapter, Indira Gandhi was the Prime Minister at this time. She had already won the Lok Sabha elections in 1971. Her personal popularity soared further after the 1971 war. After the war, assembly elections in most States took place, bringing large majorities for the Congress party in many states.

युद्ध में इस निर्णायक जीत से देश में उत्साह की लहर दौड़ गई थी। अधिकांश भारतीयों ने इसे गौरव की घड़ी के रूप में देखा और माना कि भारत का सैन्य-पराक्रम प्रबल हुआ है। आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे कि इंदिरा गांधी इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री थीं। 1971 के लोकसभा चुनावों में उन्हें विजय मिली थी। 1971 की जंग के बाद इंदिरा गांधी की लोकप्रियता को चार चाँद लग गए। इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव हुए और अनेक राज्यों में कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत से जीती।

India, with its limited resources, had initiated development planning. However, conflicts with neighbours derailed the five-year plans. The scarce resources were diverted to the defence sector especially after 1962, as India had to embark on a military modernisation drive. The Department of Defence Production was established in November 1962 and the Department of Defence Supplies in November 1965. The Third Plan (1961-66) was affected and it was followed by three Annual Plans and the Fourth Plan could be initiated only in 1969. India's defence expenditure increased enormously after the wars.

भारत ने अपने सीमित संसाधनों के साथ नियोजित विकास की शुरुआत की थी। पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष के कारण पंचवर्षीय योजना पटरी से उतर गई। 1962 के बाद भारत को अपने सीमित संसाधन खासतौर से रक्षा क्षेत्र में लगाने पड़े। भारत को अपने सैन्य ढाँचे का आधुनिकीकरण करना पड़ा। 1962 में रक्षा-उत्पाद विभाग और 1965 में रक्षा आपूर्ति विभाग की स्थापना हुई। तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) पर असर पड़ा और इसके बाद लगातार तीन एक-वर्षीय योजना पर अमल हुआ। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में ही शुरू हो सकी। युद्ध के बाद भारत का रक्षा-व्यय बहुत ज़्यादा बढ़ गया।

Fast Forward Kargil

Confrontation

In the early part of 1999 several points on the Indian side of the LoC in the Mashkoh, Dras, Kaksar and Batalik areas were occupied by forces claiming to be Mujahideens.

Suspecting involvement of the Pakistan Army, Indian forces started reacting to this occupation. This led to a confrontation between the two countries. This is known as the Kargil conflict. This conflict went on during May and June 1999. By 26 July 1999, India had recovered control of many of the lost points.

कुछ आगे की...

करगिल संघर्ष

1999 के शुरुआती महीनों में भारतीय इलाके की नियंत्रण सीमा रेखा के कई ठिकानों जैसे द्रास, माश्कोह, काकसर और बतालिक पर अपने को मुजाहिदीन बताने वालों ने कब्जा कर लिया था। पाकिस्तानी सेना की इसमें मिलीभगत भाँप कर भारतीय सेना इस कब्जे के खिलाफ़ हरकत में आयी। इससे दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ गया। इसे 'करगिल की लड़ाई' के नाम से जाना जाता है। 1999 के मई-जून में यह लड़ाई जारी रही। 26 जुलाई 1999 तक भारत अपने अधिकतर ठिकानों पर पुनः अधिकार कर चुका था।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

The Kargil conflict drew attention worldwide for the reason that only one year prior to that, both India and Pakistan had attained nuclear capability. However, this conflict remained confined only to the Kargil region. In Pakistan, this conflict has been the source of a major controversy as it was alleged later that the Prime Minister of Pakistan was kept in the dark by the Army Chief. Soon after the conflict, the government of Pakistan was taken over by the Pakistan Army led by the Army Chief, General Parvez Musharraf.

करगिल की लड़ाई ने पूरे विश्व का ध्यान खींचा था क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। बहरहाल, यह लड़ाई सिर्फ करगिल के इलाके तक ही सीमित रही। पाकिस्तान में, इस लड़ाई को लेकर बहुत विवाद मचा। कहा गया कि सेना के प्रमुख ने प्रधानमंत्री को इस मामले में अँधरे में रखा था। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज मुशर्रफ की अगुवाई में पाकिस्तानी सेना ने नियंत्रण कर लिया।

India's nuclear policy

Another crucial development of this period was the first nuclear explosion undertaken by India in May 1974. Nehru had always put his faith in science and technology for rapidly building a modern India. A significant component of his industrialisation plans was the nuclear programme initiated in the late 1940s under the guidance of Homi J. Bhabha. India wanted to generate atomic energy for peaceful purposes. Nehru was against nuclear weapons. So he pleaded with the superpowers for comprehensive nuclear disarmament.

भारत की परमाणु नीति

इस दौर की एक खास बात थी भारत का परमाणु विस्फोट। भारत ने 1974 के मई में परमाणु परीक्षण किया। तेज़ गति से आधुनिक भारत के निर्माण के लिए नेहरू ने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर अपना विश्वास जताया था। नेहरू की औद्योगीकरण की नीति का एक महत्वपूर्ण घटक परमाणु कार्यक्रम था। इसकी शुरुआत 1940 के दशक के अंतिम सालों में होमी जहाँगीर भाभा के निर्देशन में हो चुकी थी। भारत शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल के लिए अणु ऊर्जा बनाना चाहता था। नेहरू परमाणु हथियारों के खिलाफ़ थे। उन्होंने महाशक्तियों पर व्यापक परमाणु निशस्त्रीकरण के लिए ज़ोर दिया।

However, the nuclear arsenal kept rising. When Communist China conducted nuclear tests in October 1964, the five nuclear weapon powers, the US, USSR, UK, France, and China (Taiwan then represented China) – also the five Permanent Members of the UN Security Council – tried to impose the Nuclear Non-proliferation Treaty (NPT) of 1968 on the rest of the world. India always considered the NPT as discriminatory and had refused to sign it. When India conducted its first nuclear test, it was termed as peaceful explosion. India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purposes.

बहरहाल, परमाणु आयुधों में बढ़ोत्तरी होती रही। साम्यवादी शासन वाले चीन ने 1964 के अक्टूबर में परमाणु परीक्षण किया। अणुशक्ति-संपन्न बिरादरी यानी संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य भी थे, दुनिया के अन्य देशों पर 1968 की परमाणु अप्रसार संधि को थोपना चाहा। भारत हमेशा से इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता आया था। भारत ने इस पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया था। भारत ने जब अपना पहला परमाणु परीक्षण किया तो इसे उसने शांतिपूर्ण परीक्षण करार दिया। भारत का कहना था कि वह अणुशक्ति को सिर्फ शांतिपूर्ण उद्देश्यों में इस्तेमाल करने की अपनी नीति के प्रति दृढ़ संकल्प है।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

The period when the nuclear test was conducted was a difficult period in domestic politics. Following the Arab-Israel War of 1973, the entire world was affected by the Oil Shock due to the massive hike in the oil prices by the Arab nations. It led to economic turmoil in India resulting in high inflation. As you will read in Chapter Six, many agitations were going on in the country around this time, including a nationwide railway strike.

जिस वक्त परमाणु परीक्षण किया गया था वह दौर घरेलू राजनीति के लिहाज से बड़ा कठिन था। 1973 में अरब-इजरायल युद्ध हुआ था। इसके बाद पूरे विश्व में तेल के लिए हाहाकार मचा हुआ था। अरब राष्ट्रों ने तेल के दामों में भारी वृद्धि कर दी थी। भारत इस वजह से आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत में मुद्रास्फीति बहुत ज्यादा बढ़ गई। जैसा कि आप छठे अध्याय में पढ़ेंगे इस वक्त देश में कई आंदोलन चल रहे थे और इसी समय देशव्यापी रेल-हड़ताल भी हुई थी।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

Although there are minor differences among political parties about how to conduct external relations, Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties on national integration, protection of international boundaries, and on questions of national interest. Therefore, we find that in the course of the decade of 1962-1971, when India faced three wars, or even later, when different parties came to power from time to time, foreign policy has played only a limited role in party politics.

हालाँकि राजनीतिक दलों के बीच विदेश नीति के बारे में छोटे-मोटे मतभेद जरूर हैं लेकिन भारतीय राजनीति में विभिन्न दलों के बीच राष्ट्रीय अखंडता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा की सुरक्षा तथा राष्ट्रीय हित के मसलों पर व्यापक सहमति है। इस कारण, हम देखते हैं कि 1962-1971 के बीच जब भारत ने तीन युद्धों का सामना किया और इसके बाद के समय में भी जब समय समय पर कई पार्टियों ने सरकार बनाई – विदेश नीति की भूमिका पार्टी की राजनीति में बड़ी सीमित रही।

Fast Forward India's Nuclear Programme

India has opposed the international treaties aimed at non-proliferation since they were selectively applicable to the non-nuclear powers and legitimised the monopoly of the five nuclear weapons powers. Thus, India opposed the indefinite extension of the NPT in 1995 and also refused to sign the Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT).

कुछ आगे की... भारत का परमाणु-कार्यक्रम
भारत ने परमाणु अप्रसार के लक्ष्य को ध्यान में रखकर की गई संधियों का विरोध किया क्योंकि ये संधियाँ उन्हीं देशों पर लागू होने को थीं जो परमाणु शक्ति से हीन थे। इन संधियों के द्वारा परमाणु हथियारों से लैस देशों की जमात के परमाणु शक्ति पर एकाधिकार को वैधता दी जा रही थी। इसी कारण, 1995 में जब परमाणु-अप्रसार संधि को अनियतकाल के लिए बढ़ दिया गया तो भारत ने इसका विरोध किया और उसने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि (कंप्रेहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी-सीटीबीटी) पर भी हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया।

INDIA'S EXTERNAL RELATIONS भारत के विदेश संबंध

India conducted a series of nuclear tests in May 1998, demonstrating its capacity to use nuclear energy for military purposes. Pakistan soon followed, thereby increasing the vulnerability of the region to a nuclear exchange. The international community was extremely critical of the nuclear tests in the subcontinent and sanctions were imposed on both India and Pakistan, which were subsequently waived. India's nuclear doctrine of credible minimum nuclear deterrence professes "no first use" and reiterates India's commitment to global, verifiable and non-discriminatory nuclear disarmament leading to a nuclear weapons free world.

भारत ने 1998 के मई में परमाणु परीक्षण किए और यह जताया कि उसके पास सैन्य उद्देश्यों के लिए अणुशक्ति को इस्तेमाल में लाने की क्षमता है। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी परमाणु परीक्षण किए। इससे क्षेत्र में परमाणु युद्ध की आशंका को बल मिला। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी भारतीय उपमहाद्वीप में हुए इस परमाणु परीक्षण को लेकर बहुत नाराज थी और उसने भारत तथा पाकिस्तान, दोनों पर कुछ प्रतिबंध लगाए जिन्हें बाद में हटा लिया गया। भारत की परमाणु नीति में सैद्धांतिक तौर पर यह बात स्वीकार की गई है कि भारत अपनी रक्षा के लिए परमाणु हथियार रखेगा लेकिन इन हथियारों का 'प्रयोग पहले नहीं' करेगा। भारत की परमाणु नीति में यह बात दुहराई गई है कि भारत वैश्विक स्तर पर लागू और भेदभाव हीन परमाणु निशस्त्रीकरण के प्रति वचनबद्ध है ताकि परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व की रचना हो।